# आतंकवाद-ड्रग्स गठजोड़ः

## नशीले पदार्थों की तस्करी एक गंभीर सुरक्षा मुद्दा क्यों है।






दुनिया भर में नशीले पदार्थों का व्यापार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। यह एक सामाजिक समस्या है जो युवाओं और परिवारों को नुकसान पहुँचाती है और इससे उत्पन्न धन को विघटनकारी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है। इस मुद्दे ने सुरक्षा एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधर में लटका रखा है। भारत इस समस्या का कोई अपवाद नहीं है।

### ड्रग्स के प्रमुख वैश्विक क्षेत्र और भारत

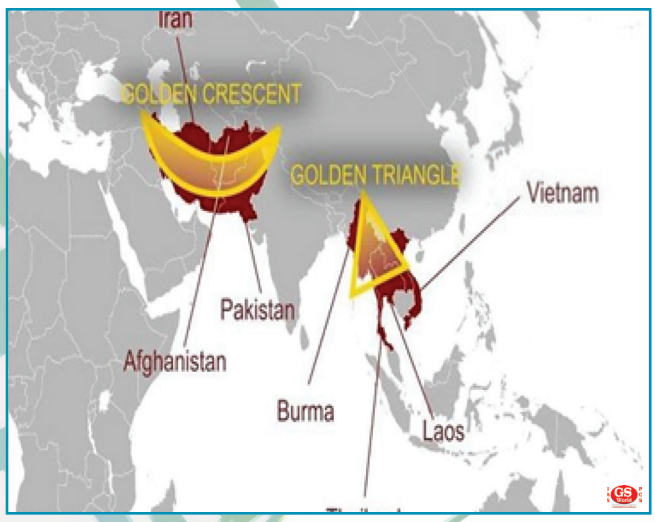

परंपरागत रूप से भारत को डेथ (गोल्डन) क्रीसेंट और डेथ (गोल्डन) ट्रायंगल के बीच सैंडविच के रूप में देखा जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से खुफिया तंत्र द्वारा समर्थित ड्रग लॉर्ड्स द्वारा इन दो क्षेत्रों से देश में ड्रग्स, विशेष रूप से हेरोइन और मेथामफेटामाइन की बाढ़ जैसी लाई जा रही है। दुनिया में इन ड्रग्स की करीब 90 फीसदी माँग इन्हीं दोनों क्षेत्रों से पूरी की जा रही है। भारत अन्य देशों के लिए एक बड़ा बाजार और एक पारगमन मार्ग दोनों है।

इस अवैध व्यापार में उत्पन्न धन असाधारण है। ऐसे संकेत हैं कि अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल पाकिस्तानी ड्रग तस्करों द्वारा अफगान अफीम को हेरोइन में बदलने के लिए किया जाता है। चीन की सीमा से सटे म्यांमार के शान और काचिन प्रांत में भी यही चुनौती सामने आती है। म्यांमार- चीन सीमा पर इन हेरोइन और मेथामफेटामाइन-उत्पादक क्षेत्रों में पारगम्य सीमाएँ हैं और कथित तौर पर विद्रोही समूहों के नियंत्रण में हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से चीनियों द्वारा समर्थित हैं। यहां अवैध हथियारों का निर्माण किया जाता है और भारत में सक्रिय भूमिगत समूहों को इसकी आपूर्ति की जाती है।

जम्मू और कश्मीर में सेना की लगातार जागरूकता ने और अनुच्छेद-370 के हटने के बाद समुद्री मार्ग भी काफी सक्रिय हो गया है। पंजाब में सीमा पार ड्रग्स और हथियारों की आपूर्ति के लिए ड्रोन का इस्तेमाल एक नई परिघटना है और कानून लागू करने वाली एजेंसियां इसे बेअसर करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार बड़ी बरामदगी कर रहा है। आईसीजी ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों बल्कि श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के तट रक्षकों के साथ भी अच्छा तालमेल विकसित किया है। इसने हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास दो अलग-अलग मामलों में 2,160 किलोग्राम मेथ जब्त किया।यह ड्रग्स म्यांमार से थाईलैंड के लिए भेजा गया था। जाँच में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे

आतंकवादी संगठनों के साथ सीमा पार से मादक पदार्थों के तस्करों के संबंध का संकेत मिला है। अवैध धन का उपयोग आईएसआई द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता है।

आश्चर्यजनक रूप से भारत कोकीन के लिए भी एक हॉट डेस्टिनेशन बन गया है, जिसकी आपूर्ति दक्षिण अमेरिकी ड्रग कार्टेल द्वारा नियंत्रित की जाती है। हाल की जांच में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग और कई यूरोपीय देशों में स्थित एनआरआई के साथ-साथ भारत में स्थानीय ड्रग लॉर्ड्स और गैंगस्टर्स के साथ इन कार्टेलों के संबंध का पता चला है, जिनके पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकवादियों और आईएसआई से संबंध हैं। इस पूरे मामले में भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह की भूमिका सवालों के घेरे में है।

## ड्रग्स के वित्तीयन और पारगमन के नए स्रोत

अध्ययनों से पता चलता है कि 62 प्रतिशत डार्कनेट का उपयोग अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा है। डार्कनेट बाजार अपनी गुमनामी और कम जोखिम के कारण पारंपरिक दवा बाजारों को बाधित कर रहे हैं।

क्रिप्टोक्यूरेंसी भुगतान और कूरियर सेवाओं के माध्यम से डोरस्टेप डिलीवरी ने डार्कनेट लेनदेन को आकर्षक बना दिया है। इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के सम्मिलित और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी। दुनिया भर में डार्कनेट का उपयोग करके अवैध व्यापार करने वालों को पकड़ने की सफलता दर बहुत कम रही है। हालांकि, जनवरी-फरवरी में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्कनेट विक्रेताओं के एक संगठित रैकेट का भंडाफोड़ किया और कई भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया।

बुनियादी पुलिसिंग विधियों के बाद तकनीकी निगरानी के कारण नशीले पदार्थों की बड़ी खेपों को जब्त किया गया और गिरोह को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शनों को उजागर किया। दुनिया भर में ड्रग कार्टेल नेटवर्क कर रहे हैं और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए बड़े पैमाने पर डार्कनेट का उपयोग कर रहे हैं, विशेष रूप से घातक रासायनिक कारकों का उपयोग करके प्रयोगशालाओं में बनाई गई फार्मास्युटिकल ओपिओइड/सिंथेटिक दवाओं के माध्यम से।

### ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए सरकारी प्रयास:

- गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स पर नकेल कसने के लिए संस्थागत संरचना की मजबूती, सभी नार्को एजेंसियों का सशक्तिकरण एवं समन्वय और विस्तृत जागरूकता अभियान का त्रिसूत्रीय फार्मूला अपनाया है।
- नवंबर 2016 में नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया है।
- नारकोटिक्स से संबंधित सभी मुद्दों के लिए एकल नोडल बिंदु के रूप में सभी उत्तर पूर्वी राज्यों ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन किया है।
- सरकार की इस दिशा में परफॉरमेंस को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने 'Whole of Government Approach' के तहत अंतर विभागीय समन्वय पर निरंतर जोर दिया है।
- सरकार द्वारा 'मादक पदार्थों के नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष' नामक फंड की स्थापना की गई।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में 'प्रोजेक्ट सनराइज' को शुरू किया गया था।
- NDPS अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। त्वरित ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित करने पर भी विचार किया गया है।

### पिछले कुछ वर्षों में ड्रग्स तस्करी को रोकने के सरकारी प्रयास के परिणाम क्या रहे हैं?

- वर्ष 2006-2013 के बीच कुल 1257 मामले दर्ज किए गए थे जो 2014-2022 के बीच 152 प्रतिशत बढ़कर 3172 हो गए। इसी अवधि में कुल गिरफ्तारी की संख्या 1362 के मुकाबले 260 प्रतिशत बढ़कर 4888 हो गई। 2006-2013 के दौरान 1.52 लाख किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई थी जो 2014-2022 के बीच दोगुना बढ़कर 3.30 लाख किलोग्राम हो गई। 2006-2013 के दरम्यान 768 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स जब्त की गई थी जो 2014-2022 के बीच 25 गुना बढ़ोतरी के साथ 20 हजार करोड़ रुपये हो गई।

एक नया चलन सामने आया है जिसमें संगठित गिरोह, जो मुख्य रूप से अपने स्थानीय क्षेत्रों में जबरन वसूली की गतिविधियों को अंजाम देते थे, इस नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, और नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जल्दी और ज्यादा पैसा उन्हें इस तरह की गतिविधियों की ओर आकर्षित करता है, लेकिन जाने-अनजाने वे विदेशों में बसे आईएसआई और खालिस्तानी तत्वों के जाल में फंस रहे हैं, खासकर कनाडा, जर्मनी, यूके, यूएसए में। इन आतंकवादी समूहों के लिए इन नेटवर्कों का उपयोग करना आसान है क्योंकि उन्हें अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पहले से तैयार लॉजिस्टिक्स मिलती है। आतंकवादियों और संगठित गिरोहों/अंडरवर्ल्ड के बीच गठजोड़ एक नई और परेशान करने वाली प्रवृत्ति है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को प्रभावी ढंग से निपटना होगा।

IAS GS World
Committed To Excellence

## संभावित प्रश्न (Expected Question)

**प्रश्न : निम्नलिखित में से कौन-सा/से देश ड्रग्स व्यापार से जुड़े स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र का हिस्सा है/हैं?**

1. थाईलैंड
2. म्यांमार
3. लाओस

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई भी नहीं

**Que. How many of the following countries is/ are part of the Golden Triangle region associated with the drug trade?**

1. Thailand
2. Myanmar
3. Laos

Select the correct answer using the code given below

(a) Only one

(b) Only two

(c) All three

(d) None

**उत्तर : C**

## संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

**प्रश्न : 'नशीले पदार्थों की तस्करी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसमे गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने हेतु भारत सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है।' टिप्पणी करें। (250 शब्द)**

**उत्तर का दृष्टिकोण :-**

- प्रश्न की शुरूआत भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी के आंकड़ों के साथ करें।
- यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती किस प्रकार है।
- इसमें गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका क्या है।
- भारत सरकार के द्वारा अभी तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों की चर्चा करें।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

**नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।**